



हर रिश्ते का रखे ख्याल...



ओसवाल का कमाल कपड़ों में डाले नई जान

ओसवाल वॉशिंग रेंज के साथ किजिये कपड़ों की ऐसी दमदार धुलाई जिससे रेशा-रेशा खिले, पर रंग न छूटे। ओसवाल से धोइए और कपड़ों को रखिए एकदम चकाचक!



बेहतर सफाई



कपड़ों की देखभाल



पैसे की बचत



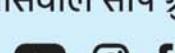
कपड़ों की चमक
व रंग बरकरार



बरसों का विश्वास



ओसवाल सोप ग्रुप



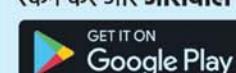
अधिक जानकारी के लिए
+91 91161 71956, 96802 01956
पर कॉल करें

विपणन:
उत्तम चंद देसराज



अब घर बैठे मँगवाए ओसवाल उत्पाद

OswalSoap.com पर जाएं या
स्कैन करें और ओसवाल एप डाउनलोड करें



राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को गलत बताया

पर, राहुल गांधी ने साथ में यह भी कहा कि, पार्टी के विचार तय होते हैं, भाजपा व संघ की तरह ऊपर से नहीं थोपे जाते

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि वे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के "बाया" से पूरी तरह असहमत हैं। जातव्य है कि पूरी "भारत जाड़ा यात्रा" में गांधी के साथ रहे दिग्विजय सिंह ने 2019 की संसदीकृत स्ट्रॉक पर एक अनोपचारिक टिप्पणी की थी।

जम्मू के झज्जर कोटी में अधिकार एक पैस कांग्रेस में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि दिग्विजय का संदर्भ बनान उनका एक विचार है। कांग्रेस इसे खारिज करता है क्योंकि "हम अपनी भारतीय सेना का सम्मान करते हैं तथा हम सेना द्वारा किये गये किसी कार्य का साक्ष्य या सबूत नहीं माँगते क्योंकि हमें अपनी सेना पर गर्व है।"

एक प्रश्न के उत्तर में राहुल ने कहा: "हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तानाशाह नहीं। हम अपनी पार्टी को दबाव वा जबरदस्ती के सिद्धांतों पर नहीं चलाते, पार्टी के विचार दिग्विजय सिंह

- उन्होंने कहा, "जब पार्टी में बातचीत होती है तो, सब तरह के विचार व मत व्यक्त किये जाते हैं, कुछ विचार गलत और उभयने वाले होते हैं, जैसा दिग्विजय सिंह के प्रकरण में हुआ, पर, उन्हें बात करने का पूरा हक व अवसर मिलता है। पार्टी उनके विचारों से कर्तव्य सहमति नहीं रखती, पर डरा-धमका कर उनको चुप नहीं कराया जाता।"
- राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि, पार्टी दिग्विजय सिंह के विचारों से नाइफाकी रखती है, कांग्रेस पार्टी सेना की बहुत हज़ारत करती है तथा अपनी कार्यवाही के लिये सेना को प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है।
- राहुल गांधी ने जोर देकर दोहराया कि, पार्टी में जब बातचीत होती है, कई अतिवादी व हास्यप्रद बातें भी कही जाती हैं, जैसा कि, दिग्विजय सिंह की टिप्पणी में साफ जाहिर हो रहा है। मुझे खेद है कि, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के बारे में यह कहना पड़ा है।

के विचार से ऊपर है। पार्टी के विचार कहा कि दिग्विजय सिंह के विचार पार्टी के अन्दर होने वाली चर्चाओं से के विचार नहीं हैं। "हम इस बात को उद्भूत होते हैं।"

उन्होंने और खारिज करते हुये सेनाएं किसी भी काम को असाधारण

रूप से अच्छी तरह करती हैं ताकि उन्हें किसी भी कार्य के लिये सबूत देने की जरूरत नहीं होती।"

दिग्विजय सिंह ने भी इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश करते हुये कहा, "मेरे मान में अपने सुरक्षा बलों के लिये आपर सम्मान है।"

राहुल गांधी ने कहा, "हमारी पार्टी की संरक्षित है कि हम विचार-विनियम एवं बातचीत की छट्ट देते हैं तथा कार्यी-कमी जब बातचीत होती है तो अतिवादी विचारों वाले लोग भी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इस बारे में जरूरत नहीं है। भाजपा और आर.एस.एस. में संबंध नहीं होता। वे बस निर्णय लेते हैं कि ऐसा होगा तथा इसके बाद कोई व्यक्ति उस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। यह सब नोटबंदी का तरह होता है। प्रधानमंत्री एक सुबह उठते हैं तथा कहते हैं कि हम नोटबंदी कर रहे हैं या फिर सब कुछ जैसे एस.टी. की तरह होता है, जिसके फलस्वरूप देश की तरह होती है। प्रधानमंत्री एक सुबह उठते हैं तथा कहते हैं कि हम नोटबंदी कर रहे हैं या फिर सब कुछ जैसे एस.टी. की तरह होता है, जिसके फलस्वरूप देश की तरह होता है।"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिजिजू ने भारी आपत्ति जताई सुप्रीम कोर्ट द्वारा जज विशेष की नियुक्ति पर सरकारी आपत्ति को सार्वजनिक करने पर

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 24 जनवरी। कांग्रेसलिंग और न्यायपालिका के बीच चल रही लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय विधि भंडी किनन रिजिजू ने आज इस बात पर कड़ा एताराज जताया कि संवैच्च न्यायालय ने उन उम्मीदवारों में जारी की गई आपत्तियों को सार्वजनिक कर दिया जिनकी जज के पद पर नियुक्ति के लिये अधिकारी को गई थी।

पिछले सप्ताह, संवैच्च न्यायालय कोलीजियम, विषय के अध्यक्ष मुख्य न्यायालय की बायां वाय. चन्द्रबूद्ध है, ने संवैच्च न्यायालय एवं आर.एस.एस. में तीन उम्मीदवार की जज के रूप में पदोन्तरित के साथ ही, उन उम्मीदवारों को सार्वजनिक कर दिया जाये या नहीं, पर फिर सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया।

- जजों का जवाब है, एक तरफ तो विधि मंत्री सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर, पारदर्शी न होने का आरोप लगते हैं, दूसरी ओर जब जज पारदर्शी होने का प्रयास करते हैं, विधि मंत्री को सुप्रीम कोर्ट के पारदर्शिता अपनाने के प्रयास पर भारी आपत्ति है।
- सरकार द्वारा तीन जजों की नियुक्ति के खिलाफ रॉ व आई.बी. के हवाले से जारी की गई आपत्तियों को सार्वजनिक करें या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में चार दिन तक मंथन चला, सरकार की आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाये या नहीं, पर फिर सार्वजनिक करने का निर्णय लिया गया।
- जजों के, इस रॉ व आई.बी. की राय को सार्वजनिक करने के कृत्य से सुरक्षा वा गुप्तचर एजेंसियों में भारी हड्कम्प भी मचा। क्योंकि इन दोनों गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाने से यह परपरा खालीपात्र होगी कि, गुप्तचर एजेंसियों की रिपोर्ट कभी भी सुविधानुसार सार्वजनिक तौर पर उत्तरागर की जा सकती है।
- सरकार का तर्क है, इस कृत्य से गुप्तचर एजेंसियों का मनोबल दूटेगा और वे स्पष्ट रिपोर्ट देने के कठरायें।

में पारदर्शिता की कमी है। वहीं दूसरी कार्यवाही पर नाराजगी भी व्यक्त कर तरफ, पारदर्शिता के खिलाफ खोले जाने रही है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के लिये उत्तरागर के नियुक्ति की नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

सरकार के साथ इस तानातीने के अपने उद्देश्य की नियुक्ति के लिये उत्तरागर के नियुक्ति की नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर के नियुक्ति की नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक्ति को नियुक्ति देने के कार्यवाही पर उत्तरागर की जज नाराजगी है।

की इस संवैच्च न्यायालय की गई व्यक



पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए पंजीकरण कराएं

उच्च मूल्य के चेक की
धोखाधड़ी से बचें।

विस्तृत जानकारी के लिए, अपनी बैंक शास्त्र में जारं या
अपने बैंक की वेबसाइट पर लौग इन करें।



आरबीआई कहता है...
जानकार बनिए,
सतर्क रहें!

अधिक जानकारी के लिए,
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/positivepay> पर जाएं
फ़िडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें

जनहित में जारी
भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

मात्र चार साल में पेपर लीक की 16-17 घटनाएं, आखिर दोषी कौन है?

विधानसभा में विपक्षी दलों के और सदन के बाहर अपनों के निशाने पर गहलोत सरकार

जयपुर, 24 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान में पेपर लीक और नकल के प्रकार को लेकर सरकार पूरी तरह से घिर गई है। विधानसभा में भाजपा और आरएसी सदरमों ने बजट सत्र शुरू होने के साथ ही सरकार की नाक में दम कर दिया है। वहीं सदक पर भाजपा के राजस्थान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार की नाक में दम कर दिया है। ऐसे में चुनावी वर्ष में सरकार के लिए पेपर लीक कांड से बाहर निकलना सबसे मुश्किल काम हो गया है। पिछले दिनों सरकार के चिन्हिण शिर्षक में मत्रियों तक ने खुलकर कहा था कि पेपर लीक का मुद्दा सरकार के सारे कामों पर पानी केर देगा।

दरअसल राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 साल के दौरान ही पेपर लीक 16 से 17 घटनाएं सामने आई हैं। ना केवल युवाओं में भारी रोप है, बल्कि विपक्षी दलों को भी सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। एक के बाद एक पेपर लीक होने और आई है। ना केवल युवाओं में भारी रोप है, बल्कि विपक्षी दलों को भी सरकार पर निशाना साधने का कोंडा आई है।

पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द होने से युवा वर्ग में भारी नाराजी है, जो चुनावी वर्ष में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है।

- मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पेपर लीक मामले में सरकारी अधिकारियों व मंत्रियों को कलीन चिट देने का हर और से भारी विरोध हो रहा है।
- पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कह ही चुके हैं कि, जब कोई दोषी नहीं तो पेपर तिजोरी से बाहर कैसे आए। कांग्रेस के ही हरीश चौधरी ने भी कह दिया है कि, इन मामलों की सी.बी.आई. जांच कराई जाए।
- भाजपा के राजस्थान सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार के सामने कई सूत्र रख दिए और अब वे सहकार पर भी उत्तर आए हैं।
- पेपर लीक के कारण परीक्षाएं रद्द होने से युवा वर्ग में भारी नाराजी है, जो चुनावी वर्ष में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है।

और अधिकारी शामिल नहीं है कि कोंग्रेस को कहाँ चाहती है और पूर्व उप मुख्यमंत्री उहोंने राजस्थान की, जो एजेंसियों जांच सचिन पायलट ने इस पर आक्रमक कर रही है तब पर अविश्वास जिता दिया तेवर अधिकारी कर रहे हैं और इस पर तिजोरी से बाहर कैसे आए। इस वज्र से परीक्षाएं रद्द करने के बावजूद भी सरकार इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पार ही है, उत्तरे अधिकारियों को कलीनचिट देने और आई है।

खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर लीक और नकल के मामलों को लेकर सरकार पर सबाल जांच विषयक और स्वतंत्र एजेंसी से उतार दिया जाए।

दरअसल सरकार की समस्या यह है कि इस मामले को लेकर चुनावी वर्ष में बदल सत्र के बाद सरकार को चुनावी तैयारियों में उत्तराधीन हो और इधर एक के काम हुई 16 से 17 पेपर लीक घटनाएं होने के बाद युवाओं की सरकार से भारी नाराजगी है। मुझ यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं कि कोई भी युवाओं की नाराजगी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यह सभी प्रक्रम में शामिल नहीं हो। ऐसे में यह बात तो उत्तर कानूनी तौर पर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

सदन में विषयक पेपर लीक कांड पर हमगामा कर रहा है और सी.बी.आई. जांच की मांग की विषयक दिया है कि मामले में यह सभी प्रक्रम कर रही है तब पर अविश्वास जिता दिया तेवर अधिकारी कर रहे हैं और इस पर तिजोरी से बाहर कैसे आए। इस वज्र से परीक्षाएं रद्द करने के बावजूद भी सरकार के लिए बाहर सहित कांग्रेस की नाक में यह बात रास नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यह सभी प्रक्रमों के बावजूद भी सरकार के लिए बाहर सहित कांग्रेस की नाक में यह बात रास नहीं होनी चाहिए।

पेपर लीक और नकल के मामलों के बावजूद भी सरकार के लिए बाहर सहित कांग्रेस की नाक में यह बात रास नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यह सभी प्रक्रमों के बावजूद भी सरकार के लिए बाहर सहित कांग्रेस की नाक में यह बात रास नहीं होनी चाहिए।

दूसरी ओर एक के बाद एक के बाद युवाओं को साथ लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और युवाओं को साथ लेकर बाहर सहित कांग्रेस की नाक में यह बात रास नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यह सभी प्रक्रमों के बावजूद भी सरकार के लिए बाहर सहित कांग्रेस की नाक में यह बात रास नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

‘पेपर लीक मामले में सी.एम.द्वारा अफसरों को कलीन चिट देना गलत’

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री गहलोत की कार्यशैली पर सवाल उठाए

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर, 24 जनवरी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में अधिकारियों को कलीन चिट देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गोप्रे की पूर्व मंत्री एवं विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

उहोंने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाए हुए साफ कहा कि जांच पूरी हुए बिंबांग से बाहर कैसे आए।

हरीश चौधरी ने मंगलवार को सदन के भीतर भी विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

उहोंने चाहिए कि यह सभी प्रक्रमों के बावजूद भी सरकार के लिए बाहर सहित कांग्रेस की नाक में यह बात रास नहीं होनी चाहिए।

हरीश चौधरी ने मंगलवार को विधायक हरीश चौधरी को बहार लगातार दिया है।

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उहोंने चाहिए कि यह एक ग्राह विरोधी

केंद्रीय कार्यालय की गोप्रे की कार्यशैली पर अपराधीय विषयक हरीश चौधरी ने गलत ठहराया है।